# समसामयिक ब्रिटिश वैदेशिक नीति

Paper-6

Dr. Khalid

Britain का ह्रास द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वह न केवल USA तथा USSR की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कम महत्वपूर्ण हो गया वरन् आगे चलकर वह महत्व की दृष्टि से चीन से भी पीछे हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति की बात तो दूर रही वह यूरोपीय राजनीति में भी प्रभाव की दृष्टि से France तथा Germany से भी पीछे रहा है। ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल में ब्रिटिश वैदेशिक नीति के निर्धारकों के समक्ष यह प्रश्न रहा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। निःसंदेह नीति निर्धारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों तथा England की बदलती हुई स्थिति ~~में परिवर्तन लाए हैं~~। 1990 वाले दशक के प्रारम्भ में शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद के काल में विशेष रूप से यूरोपीय संघ में होने वाले विकास के संदर्भ में Britain के समक्ष सामंजस्य की चुनौती उपस्थित हुई है जिसका सामना कठिन सिद्ध हो रहा है।

(margin: ...संदर्भ में (बदलते हुए) ... वैदेशिक नीति में ...ifts and readjust-... (परिवर्तन एवं ...योजन) लाया है।)

एक शक्ति के रूप में Britain के ह्रास के बावजूद वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के इरादे की घोषणा तथा खोई हुई महत्ता एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति का प्रयास भी करता है। USA के साथ घनिष्ठ संबंध की स्थापना के पीछे Britain का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है यद्यपि व्यवहार में इसका यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। यूरोप में England को केन्द्रीय स्थान दिलाने के सम्बन्ध में John Major की घोषणा तथा ~~प्रधानमंत्री Tony Blair~~ यूरोपीय राजनीति तथा राष्ट्र मंडल में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने सम्बन्धी Tony Blair की घोषणा खोई हुई प्रतिष्ठा एवं प्रभाव को प्राप्त करने की इच्छा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

(margin: ... England at the ... of Europe ... John Major ...)

यह कहा जा सकता है कि "The British foreign policy in the post war period has been reflecting the survivalist features of a declining world power."

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

Britain तथा राष्ट्र मण्डल ⇒

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

Britain की वैदेशिक नीति के अध्ययन का प्रारम्भ राष्ट्र मण्डलीय देशों के साथ Britain के सम्बंधों की व्याख्या से किया जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद Labour Party की सरकार ने उपनिवेशों के सम्बंध में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और उन्हें एक-एक करके स्वतंत्र करना शुरू किया। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उपनिवेशों को स्वतंत्र करने में उसका उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन परिस्थितियों तथा उसके राष्ट्र हित के विचार से प्रेरित था। USA तथा USSR का महाशक्ति के रूप में उदय हुआ तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से Britain का ह्रास हुआ। दयनीय आर्थिक स्थिति तथा उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि ~~को अक्षुण्ण~~ के उपनिवेशों को अक्षुण्ण बनाए रखना Britain के लिए सम्भव नहीं था। उसने उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाने की नीति भी अपनाई और इस तरह वह उन पर कुछ हद तक अपना राजनीतिक प्रभाव रखना चाहता था। 1960 वाले दशक में Britain की राष्ट्रमण्डलीय नीति सही भी सिद्ध हुई। किन्तु 1960 वाले दशक के उत्तरार्द्ध से लेकर अबतक की प्रवृत्तियों को देखने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि राष्ट्रमण्ड के साथ ब्रिटेन के पुराने संबंध अब लुप्त होते जा रहे हैं। इंडोनेशिया के संकट में Britain की भूमिका तथा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार के प्रति पक्षपात-पूर्ण नीति ने अधिकांश राष्ट्रमण्डलीय देशों को Britain ने नाराज कर दिया।

Britain की नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कई अवसरों पर राष्ट्रमण्डलीय देशों ने उसे पाखण्डी घोषित किया है। 1970 वाले दशक के प्रारम्भ से ~~लेकर 1990 वाले~~ लेकर 1990 दशक में दक्षिण अफ्रीका में Nelson Mandela के नेतृत्व में सरकार के गठन के पूर्व तक राष्ट्रमण्डलीय देशों के शासनाध्यक्षों के जितने भी सम्मेलन हुए उनमें Britain की नीति की आलोचना हुई। दक्षिण अफ्रीका के प्रति ब्रिटिश नीति के एक असफल

यदि ब्रिटेन एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के राष्ट्रमण्डलीय देशों के मनोकूल दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करता तो निश्चित रूप से

उन देशों के नजर में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। वर्तमान समय में तो आस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन के पारस्परिक आर्थिक देश में भी ब्रिटेन ने USA के साथ घनिष्ठतम संबंध बनाये रखने का प्रयास किया है। दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्यतः विशेष संबंध (Special Relation) का नाम दिया जाता है। 1970 वाले दशक में यह विशेष संबंध कुछ ढीला होता हुआ प्रतीत होता था परन्तु 1979 में Thatcher के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ब्रिटेन का अमेरिका के साथ विशेष संबंध फिर से स्थापित हो गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन काफी तत्पर था। उधर अमेरिका भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति का अवलम्बन कर रहा था। ब्रिटेन स्वयं आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया था और पश्चिमी यूरोप के अन्य देश भी इस स्थिति में नहीं थे कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या यहाँ तक कि यूरोपीय राजनीति में भी सोवियत प्रभाव को रोक सकें। ब्रिटेन पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए तथा सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए भी अमेरिका के सहयोग एवं नेतृत्व को आवश्यक मानता था। Leon-D-Epstein ने उचित ही कहा है कि

ब्रिटेन ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद शायद ही अपनी वैदेशिक नीति में अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होकर कार्य किया हो। कुवैत संकट से लेकर 2001 में अफगानिस्तान पर सैनिक कार्यवाही तथा 2003 में इराक के विरुद्ध USA की नीति का अनुसरण किया है। इसमें ब्रिटेन की छवि एक पीछलगु देश की बनी है। आज आतंकवाद के नाम पर ब्रिटेन अपनी स्वतंत्र सोच के स्थान पर अमेरिकी सोच तथा नीति का समर्थन कर रहा है।

यद्यपि ब्रिटेन पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ सहयोग के लिए तत्पर था तथापि अन्य उद्देश्यों से प्रेरित होकर वह यूरोपीय प्रतिरक्षा संधि तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित नहीं हुआ। परन्तु यूरोपीय देशों के संगठन विशेष रूप से EEC से अलग रहने के चलते उसे कई प्रकार की

आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

यद्यपि ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय समुदाय का सदस्य हो गया तथापि इसके प्रति ब्रिटिश नीति में असंगति एवं आशंकापूर्ण स्थिति बनी हुई है। 1979 में Thatcher के प्रधानमंत्री बनने के बाद Britain तथा EEC के बीच का सम्बन्ध नये सिरे से वाद विवाद का विषय बन गया। यह वाद विवाद 1990 वाले दशक में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों के द्वारा आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण के लिए सम्पन्न किये गये Maastricht Treaty (1992) से लेकर 2019 तक में प्रयासों के सम्बन्ध में British दृष्टिकोण के चलते बना हुआ है। 1997 के आम निर्वाचन के साथ आंतरिक राजनीति में एकीकरण के विरोधियों तथा समर्थकों के बीच गम्भीर विवाद देखने को मिला। European Monetary Union (यूरोपीय मुद्रा संघ) के लिए जिस Euro नामक Single Currency को जनवरी 1999 में लागू करने के लिए 1998 में समझौता हुआ Britain उससे अलग रहा। यद्यपि Britain ने यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया के प्रति Britain के परम्परागत आशंकापूर्ण दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए उत्सुकता जाहिर की है। परन्तु वैसा कुछ हुआ नहीं जिससे ~~स्पष्ट साबित हो कि~~ यूरोप के प्रति Britain की नीति ~~के चलते यूरोपीय संघ में के सदस्य देशों में Britain विश्वसनीयता में कमी आयी है~~ परिवर्तन की उत्सुकता जाहिर हो। यूरोपीय संघ के प्रति.x.

साम्यवाद विरोधी होने के चलते एक लम्बी अवधि तक Britain ने सोवियत संघ विरोधी नीति का अवलम्बन किया है। 1985 में Gorbachev को सोवियत साम्यवादी दल के शीर्ष नेता के रूप में उदय तथा उसके द्वारा आंतरिक राजनीति में Glasnost और Perestroika ~~वैदेशिक नीति~~ के अनुरूप New thinking (नई सोच) के समावेश सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सोवियत संघ के सर्वप्रमुख उत्तराधिकारी राज्य रूस के साथ सम्बन्धों को पूर्णतः पर सामान्य कहा जा सकता है। रूस में जनजात उदारवादी जनतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण का ब्रिटेन ~~Britain~~ पक्षधर रहा है।

जिस देश तथा क्षेत्रों के प्रति British दृष्टिकोण की चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त विश्व के अन्य क्षेत्रों के प्रति ब्रिटिश नीति पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि Britain ने अपनी भूमिका एवं नीति

आशंकापूर्ण

ब्रिटेन की नीति में असंगति एवं आशंकापूर्ण स्थिति के चलते ब्रिटेन की विश्वसनीयता में कमी आई है।

वैदेशिक नीति में

SHOT ON REDMI
AI DUAL CAMERA
Scanned with CamScanner

USA की भूमिका एवं नीति के अधीन कर दिया है।

2003 में इराक के प्रति सैनिक कार्यवाही में Britain द्वारा USA का साथ इसका नवीनतम उदाहरण है। ~~Labour विजय की आलोचना तथा उसपर~~ अमेरिका का पीछलग्गू होने के आरोप के बावजूद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

2006 में हिजबुल्लाह एवं इजराइल के बीच के संघर्ष तथा फिलीस्तीन के प्रश्न पर Britain की नीति अमेरिका के समर्थन मात्र की रही है। यदा कदा Britain द्वारा अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होकर वैदेशिक क्षेत्र में उठाए गए कदम, उसके प्रभाव में रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति की तुलना में बहुत ही कम महत्व के हैं। ऐसी स्थिति में Britain यूरोपीय राजनीति में केन्द्रीय स्थान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका तथा राष्ट्रमण्डल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा की प्राप्ति की बात खोखली प्रतीत होती है।